साप्ताहिक

RNI-MPHIN/2015/72544

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार 16-22 मई 2023 वर्ष-9, अंक-5

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

गौ-रक्षा संकल्प सम्मेलन: सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 406 एंबुलेंस को दिखाई हरी झंडी, और की घोषणा

गाय का गोबर भी खरीदेगी सरकार एक कॉल पर पशु एंबुलेंस हाजिर!

» मुख्यमंत्री ने कहा-अब पशुओं के इलाज के लिए भी उपलब्ध होगी एंबुलेंस

» पशु एम्बुलेंस बुलाने के लिए जारी किया टोल फ्री नम्बर-1962

» गौ माता को बचाने के लिए सरकार के साथ समाज को भी जुटना पड़ेगा

» गौशाला प्रबंधन के लिए अपर कलेक्टर स्तर का अधिकारी तैनात होगा

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्यप्रदेश में अब बीमार और घायल गौवंश को इलाज मुहैया कराने एक फोन पर एंबुलेंस मुहैया होगी। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर आयोजित गौ-रक्षा संकल्प सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि 1962 नंबर पर फोन करेंगे तो पशु चिकित्सा एंबुलेंस वहां पहुंच जाएगी, जहां बीमार गौमाता है। चलता फिरता अस्पताल उन तक पहुंच जाएगा। हर एक ब्लॉक के लिए अलग एंबुलेंस रहेगी।

गौशाला से फोन आए या किसी किसान या गौपालक के घर..तत्काल एंबुलेंस पहुंच जाएगी और इलाज करने का काम करेगी। शिवराज ने प्रदेश के किसानों से गाय का गोबर खरीदने का एलान किया है। हर साल गौ-रक्षक सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। सरकार किसान से गाय का गोबर भी खरीदेगी और किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाएगी। गोबर से प्लांट में बायो सीएनजी गैस बनाएंगे। जबलपुर में प्लांट सितंबर में पूरा हो जाएगा। इसके बाद जगह-जगह प्लांट लगातार सरकार गोबर खरीदेगी।

गाय खरीदने पर सब्सिडी

सरकार ने मध्यप्रदेश में गौ-वंश के वध पर प्रतिबंध लगाने का काम किया है। अगर कोई यह पाप करेगा तो उसे 7 साल की सजा दी जाएगी। गौ-वंश के अवैध परिवहन के मामले में भी दोष सिद्ध होने पर कार्रवाई की जाएगी। प्राकृतिक खेती करने वाले गौ-पालकों को 900 रुपए प्रति माह गाय पालन के लिए दिए जाएंगे। ऐसे 22,000 किसानों को हम इसी महीने 900 रुपए की किस्त जारी कर रहे हैं। आदिवासी आदिवासी क्षेत्रों में गाय खरीदेंगे और गौ-पालन करेंगे तो दो गायों के लिए उन्हें 90 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी।

406 एंबुलेंस आवंटित

प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों के लिए 406 एंबुलेंस आवंटित की गई हैं। हर एंबुलेंस में एक पशु चिकित्सक, पैरावेटरिनरी स्टाफ और सहायक संचालक होंगे। कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर 1962 आप नोट कर लें। पिछले चुनाव में हमने वादा किया था और इसे पूरा कर दिया।

गौ-पालन से महिलाओं की भी बढ़ेगी आमदनी

भाजपा के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने कहा कि मप्र गौ-रक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य है। गौ-रक्षा का मतलब मुस्लिमों का विरोध करना नहीं है। गाय की रक्षा का मतलब मुसलमान का विरोध कहां से हो गया। गौ-रक्षा, गौ-सेवा की बात करना सेक्युलरिज्म का विरोध करना नहीं है। शिवराज, मोदी और भाजपा की सरकारें भारत की संविधान की मूल आत्मा के अनुरूप मानकर गौ-रक्षा का काम करती हैं। गाय की सेवा लाड़ली बहना की सेवा है। दुग्ध उत्पादन से लेकर विपणन के काम में महिलाएं जुड़ीं हुई हैं। आने वाले दिनों में महिलाओं की आमदनी बढ़ाने के लिए कोई प्रकल्प है तो वह गाय के माध्यम से हो सकता है।

अखिलेश्वरानंद ने 5 मांग रखीं

गौ संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष अखिलेश्वरानंद गिरी ने समारोह के दौरान सरकार के समक्ष पांच मांगें रखीं। **पहली**-अविभाजित मप्र में दस गौ-सदन हुआ करते थे। विभाजन के बाद दो गौ-सदन छग चले गए। बचे 8 गौ-सदनों की मप्र के जंगलों में 6700 एकड़ जमीन है। गौ-सदन भंग कर दिए गए, अब इस भूमि पर नए कलेवर में गौ-वंश विहार विकसित करें। **दूसरी**-मनरेगा की सहायता से तैयार गौ-शालाओं की 5-5 एकड़ जमीन अतिक्रमण की चपेट में हैं। इन्हें अतिक्रमण मुक्त कराएं। **तीसरी**-गौ-शालाओं में बिजली का बिल एक हजार रुपए कम तक कम किया जाए। **चौथी**-गौ-शालाओं में तैयार वर्मी कम्पोस्ट, जैविक खाद खरीदना वानिकी, उद्यानिकी, नगरीय प्रशासन जैसे सरकारी विभागों के लिए अनिवार्य किया जाए। **पांचवीं**-गौ-शालाओं में तैयार प्राकृतिक पेंट, गौनाइल का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी भवनों की पुताई-सफाई में अनिवार्य किया जाए।

कैबिनेट का अहम फैसला-किसानों को लाभ लेने 30 नवंबर 2023 तक करना होगा आवेदन

प्रदेश के 11 लाख डिफॉल्टर किसानों का 2123 करोड़ ब्याज माफ

भोपाल। जागत गांव हमार

प्रदेश सरकार ने डिफॉल्टर किसानों को राहत देने वाला निर्णय लिया है। सरकार 11 लाख 19 हजार डिफॉल्टर किसानों पर बकाया ब्याज की राशि 2123 करोड़ को माफ करने के लिए ब्याज माफी योजना को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में ब्याज माफी योजना को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो किसान ऋण माफी के चक्कर में डिफॉल्टर हो गए हैं, उनके ब्याज की राशि सरकार द्वारा भरी जाएगी। इसका लाभ जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) के ऐसे डिफॉल्टर किसानों को मिलेगा, जिनका 31 मार्च 2023 की स्थिति में मूल एवं ब्याज मिला कर दो लाख तक का ऋण बकाया है। ब्याज माफी होने के बाद भी किसानों को 3356 करोड़ रुपए का मूलधन चुकाना होगा।

खंडवा-छतरपुर-देवास में नया अनुविभाग

कैबिनेट ने खंडवा जिले में खालवा, छतरपुर में गौरीहार और देवा में टोंकखुर्द में नवीन अनुविभाग सृजन की स्वीकृति दी। राजस्व विभाग की वेबजीआईएस 2.0 परियोजना लागू करने के लिए वर्ष 2028 तक 129 करोड़ 32 लाख रुपए के व्यय करने की मंजूरी दी।

खंडवा, छतरपुर और देवास में नवीन अनुविभाग को मिली मंजूरी राजस्व विभाग की परियोजना के लिए 129 करोड़ 32 लाख स्वीकृत

30 नंवबर तक करना होगा आवेदन

ब्याज माफी का लाभ लेने डिफॉल्टर किसानों को अपनी समिति में आवेदन करना होगा। इसके लिए अंतिम तारीख 30 नवंबर 2023 तय की गई है। इसके बाद डिफॉल्टर किसानों के ऊपर बकाया ऋण एवं ब्याज आदि के विवरण वाली सूची को बैंक स्तर पर एक पोर्टल से सार्वजनिक किया जाएगा। साथ ही योजना में किसानों को कृषि कार्य के लिए खाद उपलब्ध कराने की विशेष सुविधा दी गई है। जितनी राशि किसान द्वारा अपने ऋण खाते में नगद जमा की जाएगी। उतनी राशि तक का खाद वे समिति से ऋण के रूप में प्राप्त कर सकेंगे।

रीवा हवाई पट्टी पर बनेगा हवाई अड्डा

कैबिनेट ने रीवा हवाई पट्टी पर हवाई अड्डा बनाने को लेकर चर्चा की। इसके लिए भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी योजना में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने के लिए प्राधिकरण और राज्य शासन के बीच एमओयू करने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने जल संसाधन विभाग वार्ड -2 लवकुश नगर की परिसम्पति को निविदा में सर्वाधिक बोली लगाने वाले को देने को लेकर चर्चा की।

2018 से 2021 का मामला: रेंडम जांच में कई खाते मिले सस्पेक्टेड, जिम्मेदारों पर अब गिरेगी सरकार की गाज

नाजिर, पटवारी और ऑपरेटर दोषी, होगी एफआईआर दर्ज

तीन सौ किसानों की दूसरे खातों में डाल दिए राहत के 47 लाख रुपए

भोपाल। जागत गांव हमार

सीहोर जिले के 500 किसानों के खातों में 3 साल से फसल क्षतिपूर्ति की राशि नहीं आई और शासन को यह बता दिया गया राशि खातों में पहुंचा दी गई है। यह राशि 2 करोड़ की थी। ये गड़बड़ी महालेखाकार ग्वालियर के ऑडिट में किसानों के नाम मिसमेच होने से सर्व में आमने आई थी। इस मामले में इछावर के नाजिर,पटवारी और ऑपरेटर को दोषी मानकर एफआईआर करने की तैयारी है। ठीक वैसा ही मामला अब विदिशा जिले में सामने उजागर हुआ है। यहां जिले की 4 तहसीलों में किसानों के हक की 47 लाख रुपए से अधिक की राहत राशि का गबन हुआ है। महालेखाकार कार्यालय में राहत राशि वितरण की जब रेंडम ली जांच के लिए फिल्टर लगाया गया तो कई खाते सस्पेक्टेड पाए गए, जिनमें नाम किसी और किसान का और खाता किसी दूसरे का पाया गया। अब इस मामले की जांच चल रही है। इसके बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है।

सूखा-अतिवृष्टि की क्षतिपूर्ति राशि

वर्ष 2018 से 2021 तक के बीच राहत राशि वितरण में यह घोटाला हुआ है। प्राकृतिक आपदा सूखा, मूसलाधार बारिश, अतिवृष्टि, कीट प्रकोप आदि के तहत शासन से स्वीकृत राहत राशि हितग्राहियों के बजाए दूसरे खातों में या गलत खातों में डालकर निकाला गया है। शमशाबाद, गुलाबगंज, कुरवाई, लटेरी तहसील में यह फर्जीवाड़ा हुआ है। इस तरह की गड़बड़ियां इन्हीं वर्षों में और बाद के वर्षों में शासन से स्वीकृत होकर जिले में वितरित हुई फसल क्षति व अन्य क्षतिपूर्ति के मामलों में भी होने से इंकार नहीं किया जा सकता है।

रिश्तेदारों के खातों में डली राशि

प्रारंभिक जांच में यह जानकारी सामने है कि यह राशि स्थानीय पटवारी, नाजिर, ऑपरेटर, चौकीदार और उनके रिश्तेदारों के खातों में या गलत खातों में डालकर निकाली गई है। हैरत की बात यह है कि शासन द्वारा किसानों को स्वीकृत की गई राहत राशि वितरण में हुई गड़बड़ी संबंधित तहसीलों के वरिष्ठ राजस्व अधिकारियों की पकड़ में क्यों नहीं आई यह समझ से परे है। इस मामले में वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर मैदानी अमले की मिली भगत से लाखों का गबन होने से इंकार नहीं किया जा सकता है। महालेखाकार के आदेश पर विदिशा जिले की तहसीलों में हुए इस गबन की जांच की जा रही है। मामले की जांच पूरी होने के बाद कार्रवाई होने की बात कही जा रही है।

13 बार तक राशि का ट्रांजेक्शन

विदिशा जिले में 300 से ज्यादा खाते ऐसे मिले हैं, जिनमें राहत राशि के लिए हितग्राही का नाम और जिस खाते में राशि जमा हुई उस खाताधारक का नाम अलग-अलग निकला है। इन 300 हितग्राहियों के हक की राशि 41 लोगों के खातों में डालकर निकाला गया है। हद तो यह है कि जिन खातों में राशि डालकर निकाली गई है, उनमें से कई खातों में तो कहीं 3 से लेकर 13 बार राहत राशि का ट्रांजेक्शन हुआ है। एक व्यक्ति के खाते में 13 हितग्राहियों तक की राशि डालकर निकाली गई है। हकीकत में यह राहत राशि वास्तविक प्रभावित किसानों के खातों में पहुंची ही नहीं। वास्तविक प्रभावित किसान राहत राशि के लिए सीएम हेल्प लाइन और जिले के जिम्मेदार अधिकारियों के पास आवेदन देकर चक्कर काटते रहे।

-पांच साल पहले सालगिरह पर शुरू किया, अब तक 20 हजार पौधे बांट व लगा चुके

इंदौर को फलदार सिटी बनाने की पहल

इंदौर। जागत गांव हमार

इंदौर को फलदार शहर बनाने की कोशिश दो दोस्तों ने मिलकर शुरू की है। पिछले पांच सालों से ये दोनों लोग इंदौर में फलदार पौधे बांटने और लगाने का काम कर रहे हैं। अब तक करीब 20 हजार से ज्यादा फलदार पौधे बांट और लगा चुके हैं। खास बात यह है कि वे फ्री में लोगों को पौधे उपलब्ध कराते हैं और उसके साथ खाद भी मुफ्त ही देते हैं। ये शख्स है इंदौर के जानकी नगर में रहने वाले गौतम जैन। गौतम जैन प्रॉपर्टी व्यवसायी हैं, वे अपने दोस्त हेमंत जैन के साथ पिछले पांच सालों से अनूठा काम इंदौर में करते आ रहे हैं। इन दोनों का यहीं उद्देश्य है कि वे प्रकृति के लिए कुछ करें और उसे ज्यादा से ज्यादा लौटा सकें और इंदौर को फलदार सिटी बना सकें।

सात साल पहले जब गौतम अपने परिवार और दोस्तों के साथ घूमने गए थे, तब देहरादून होते हुए चंडीगढ़ भी जाना हुआ। उन्होंने वहां घरों में फलदार पेड़ और उनके फल देखे। जिसे देख उनके मन भी ये ख्याल आया कि क्यों न अपने शहर को भी इस तरह से बनाया जाए। वहां से लौटने के करीब दो साल तक वे इस पर विचार और दोस्तों-परिवारों से चर्चा की। गौतम जैन ने 12 दिसंबर 2017 को अपनी शादी की 25वीं सालगिरह पर एक आयोजन किया। जिसमें अपने परिवार और दोस्तों को बुलाया। इस आयोजन में गौतम और उनकी पत्नी ने 800 फलदार पौधे बांटे। इसके बाद से फलदार पौधे बांटने और लगाने का सिलसिला शुरू हो गया।

अब तक 20 हजार पौधों का वितरण

गौतम जैन बताते हैं कि शादी की सालगिरह पर शुरू हुआ ये सिलसिला लगातार जारी है। वे पिछले पांच सालों में करीब 15 हजार फलदार पौधे बांट चुके हैं और करीब 4 से 5 हजार पौधे खुद लगा चुके हैं। कई पौधे वे बगीचों, मल्टी स्टोरी टाउनशिप, खेतों आदि स्थानों पर लगा चुके हैं। उन्होंने बताया कि शादी की सालगिरह पर तो वे 5 से 10 फलदार पौधे लगाते हैं, मगर 21 जून को योग दिवस के मौके पर वे अग्रसेन चौराहे पर करीब 2 हजार से ज्यादा फलदार पौधों का वितरण करते हैं। इसके अलावा वे राखी के मौके पर भी पौधों का वितरण करते हैं।

ये फलदार पौधे बांटते हैं

गौतम जैन आम, जाम, जामुन, आंवला, चीकू, नींबू, अनार, सीताफल, फालसे सहित अन्य किस्म के फलदार पौधों का वितरण करते हैं। उनका मानना है कि जब लोगों को ये फलदार पौधे आसानी से उपलब्ध होते और वे खुद लेने आते हैं तो वे इन फलदार पौधों का खास ध्यान भी रखते हैं। साथ ही वे पौधे लेने वालों से भी अपील करते हैं कि वे पौधों का ध्यान रखे, ताकि प्रकृति का ऋण चुका सके। उन्होंने सभी से अपील भी की है कि व्यक्ति एक फलदार पौधा लगाए।

15 से घर से वितरित करेंगे

गौतम जैन ने अपना खुद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया। जिसमें उन्होंने लोगों को मुफ्त में फलदार पौधे देने की बात कहीं है। साथ ही कहा कि 15 मई से वे घर से फलदार पौधें वितरित करने का काम शुरू करेंगे। सोमवार को वे विभिन्न किस्म के फलदार पौधे लेकर आए हैं। उन्होंने बताया कि वे इंदौर और आसपास की नर्सरी से ये फलदार पौधे लेकर आते हैं। उनका सिर्फ यहीं उद्देश्य है कि इंदौर फलदार सिटी बने। उनका मानना है कि फलदार पौधे लगाने से उसमें जब फल आएंगे तो लोगों से लेकर पशु-पक्षी सभी उसे खाएंगे। इसके साथ ही वह छाया भी देंगे और इससे शहर की वातावरण भी अच्छा होगा है। घर से पौधे वितरित करने का काम भी कई सालों से करते आ रहे हैं। उनके यहां पौधे लेने के लिए कई लोग आते हैं। वे फलदार पौधे देने के साथ-साथ उन्हें खाद का पैकेट भी देते हैं ताकि वे जाकर सीधे पौधे को गमले में खाद डालकर लगा सकें।

दो गुना से अभी अधिक भाव में बिक रहा

खंडवा में अदरक 200 रुपए किलो तक पहुंचा

खंडवा। जागत गांव हमार

मसालेदार सब्जियों में सबसे अधिक उपयोग में लाए जाने वाले अदरक के भाव आसमान छू रहे हैं। बाजार में अदरक 200 रुपए किलो तक बेचा जा रहा है। ग्राहक भाव सुनकर ही मन मसोस रहे हैं। इधर हरा धनिया के भाव भी बढ़े हुए हैं। फुटकर विक्रेता करीब 40 रुपए किलो तक हरा धनिया बेच रहे हैं। आमतौर पर 70 से 80 रुपए किलो तक बिकने वाला अदरक दो गुना से भी अधिक भाव में बेचा जा रहा है।

इतने दाम में अदरक कभी नहीं बेचा- खंडवा के बुधवारा स्थित बाजार में सब्जी खरीदने के लिए आने वाले ग्राहक अदरक के भाव सुनकर ही कतरा रहे हैं। सब्जी विक्रेता यूसूफ लाला ने बताया कि इतने अधिक दाम में अदरक हमने कभी नहीं बेचा। सामान्य रूप से 15 से 20 रुपए का 250 ग्राम अदरक हमेशा बिकता है। जिले में उत्पादन कम होने के कारण अदरक की आवक कर्नाटक और महाराष्ट्र से हो रही है। भाव बढ़ने का एक प्रमुख कारण यह भी है। इधर सहायक उद्यानिकी अधिकारी योगेश यादव का कहना है कि जिले में अदरक की खेती बहुत कम होती है।

अदरक का उत्पादन कम होने से बढ़े भाव

मुश्किल से आठ से दस हेक्टेयर में अदरक किसानों द्वारा लगाया जाता है। संयुक्त कृषक संगठन के जिलाध्यक्ष नरेंद्र पटेल का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों से मंडी में अदरक का भाव कम मिलने से अदरक की पारंपरिक खेती करने वाले किसानों ने भी इस वर्ष अदरक लगाने से परहेज किया। उत्पादन कम होने से भी भाव बढ़े हैं। इधर मंडी में हरा धनिया 50 रुपए किलो बेचा जा रहा है। हालांकि सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि हरा धनिया पर उतनी महंगाई नहीं है। वहीं लहसून के भाव 100 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं।

ऑनलाइन रिसर्च की, डॉक्यूमेंट्री देखी, खेती के दूसरे फार्म तलाशे

अहमदाबाद, बड़ौदा और गुड़गांव के फार्म की विजिट किए दोनों ने

एक एकड़ में चार एकड़ जितनी उगा रहे सब्जियां

इंदौर। जागत गांव हमार

एक एकड़ में 4 एकड़ जितनी खेती और प्रोडक्शन। मिट्टी की जरूरत नहीं, पानी भी सामान्य खेती की तुलना में मात्र 20 प्रतिशत और लागत भी बेहद कम। ये सारी खूबियां हैं हाइड्रोपोनिक खेती की। इसे इंदौर में एक कपल ने शुरू किया है। तकनीक इजराइल में विकसित हुई है, जहां खेत कम हैं इसलिए घरों में ऐसी खेती होती है। यह तकनीक भारत में अभी केवल सब्जियों तक सीमित है। कपल का लॉकडाउन वाला ये स्टार्टअप अब 1 करोड़ कमाई वाले क्लब में पहुंच गया है। यह मध्यप्रदेश में कमर्शियल लेवल का पहला बड़ा फार्म है। वे लोगों को खेती की यह तकनीक तो सिखाते ही हैं, अपने खेत से सब्जियां तोड़ने का मौका भी देते हैं। इस दंपती का नाम है ऋषभ मेहता (29) और पूजा (26) जो संगम नगर में रहते हैं। दरअसल, किस्सा सात साल पहले का है। ऋषभ तब 22 साल के थे। उन्हें विटामिन बी 12 और डी 3 की कमी हो गई। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने सप्लीमेंट्स लिख दिए। सप्लीमेंट्स लेने से पहले ही ऋषभ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कमर्शिलाइजेशन की पढ़ाई के लिए 2017 में ऑस्ट्रेलिया चले गए। वहां गए और कुछ दिनों बाद जांच कराई तो पता चला कि विटामिन बी12 और डी 3 की कमी दूर हो गई है। बिना सप्लीमेंट्स के ये कमी दूर होने पर उन्हें शंका हुई। उन्होंने जानकारी जुटाई तो पता चला कि ऑस्ट्रेलिया में जो सब्जियां वो खा रहे थे उनमें पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स और विटामिन हैं। ऋषभ भारत लौटे तो उन्हें विटामिन बी12 और डी3 की फिर से कमी हो गई। ऋषभ बताते हैं भारत में पेस्टिसाइड्स का अधिक उपयोग होने के कारण नेचुरल मिनरल-विटामिन नष्ट हो जाते हैं, इसलिए हमें कई बीमारियां हो जाती हैं और हम कम उम्र में ही बीमार रहने लगते हैं।

अब बात उनके स्टार्टअप की

ऋषभ बताते हैं कि आने वाले समय में भारत में भी जमीन की कमी हो जाएगी, इसलिए खेती के विकल्पों पर अभी से काम करने की जरूरत है। यही सोचकर हमने हाइड्रोपोनिक फार्मिंग की ओर कदम बढ़ाए। पत्नी और परिवार से बात करने के बाद इस दिशा में कदम बढ़ाया। हमने एक साल पहले यानी मार्च 2022 में नेमावर रोड पर एक करोड़ रुपए के निवेश के साथ इकारिया फ्रेश के नाम से इस खेती की शुरुआत की। इसे शुरू करने से पहले ऑनलाइन रिसर्च की, डॉक्यूमेंट्री देखी, उन्होंने इस तरह से खेती करने वाले दूसरे फार्म तलाशे। अहमदाबाद, बड़ौदा और गुड़गांव के फार्म विजिट किए। ऑनलाइन कोर्सेस भी किए।

नाम रखा इकारिया

पूजा और ऋषभ ने बताया कि दुनिया में 5 ऐसी चिन्हित जगह है जहां की शुद्ध आबो-हवा और पौष्टिक खान पान की वजह से वहां दुनिया के सबसे उम्रदराज लोग स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीते हैं। इन जगहों को ब्लू जोन रीजन कहा जाता है। इनमें से एक ग्रीस देश में एक जगह है इकारिया है। इकारिया एक ऐसी जगह है जहां हर तीसरा व्यक्ति 90 साल की उम्र तक स्वस्थ जीवन जीता है। हमारा मानना है कि हम पौष्टिक सब्जी और साफ वातावरण में उगाई गई सब्जी से इकारिया का जादू देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में लाए हैं।

पूरे इंदौर में डिलीवरी

ऋषभ और पूजा ने बताया कि वे इन सब्जियों के सैलेड के बॉक्स भी तैयार करके सेल करते हैं। इस बॉक्स में वे सैलेड के साथ उसमें ऊपर से डालने के लिए लिक्विड मसाले भी देते हैं। इनके इन बॉक्स की बात करें तो 130 रुपए से लेकर 500 रुपए तक के बॉक्स उपलब्ध हैं। इसमें 299 रुपए से ऊपर के ऑर्डर पर वे फ्री होम डिलीवरी करते हैं।

सब्जियों की टैग लाइन

- » 130 रुपए में 120 ग्राम (एक टाइम में एक व्यक्ति के लिए)
- » 299 रुपए में 300 ग्राम (दो व्यक्ति तीन बार के लिए)
- » 349 रुपए में 350 ग्राम (दो व्यक्ति तीन बार के लिए)
- » 500 रुपए में 500 ग्राम (दो लोग 5 दिन तक)

हर माह 3 से 5 लाख तक की सेल कर रहे

ऋषभ को ये भी चिंता थी कि इंदौर में सब्जियों के लिए मोलभाव होता है ऐसे में ये सब्जियां कौन खरीदेगा। इस सवाल के जवाब में ऋषभ और उनकी पत्नी पूजा ने सात सौ से ज्यादा लोगों से बात की। इन सब्जियों के बारे में बताया। लोगों को जागरूक करने और बिजनेस को बढ़ाने के लिए डिजिटल एड और सोसाइटी कैंप भी लगाए। पूजा कहती हैं कि कोविड के कारण लोग अपने स्वास्थ्य पर भी खर्च करने लगे हैं, इसलिए मुझे लोगों को समझाने में ज्यादा समस्या नहीं आई। लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो गए हैं, इसलिए हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उनकी सब्जियां शहर के सभी प्रमुख स्टोर पर उपलब्ध हैं। वे इस बिजनेस से हर माह 3 से 5 लाख तक की सेल कर रहे हैं।

हाइड्रोपोनिक फार्मिंग यानी सॉयल-लेस फार्मिंग

हाइड्रोपोनिक फार्मिंग यानी सॉयल-लेस फार्मिंग। इसके लिए जमीन यानी मिट्टी की जरूरत नहीं होती है। जमीन की जगह पाइप या स्टैंड में प्लांटिंग की जाती है। पौधों की जड़ें इसी पानी में रहती है। पौधे के लिए जरूरी मिनरल और विटामिन लिक्विड फॉर्म में पानी के जरिए पौधों को मुहैया कराए जाते हैं। पानी को आरओ मशीन से फिल्टर किया जाता है। इससे कम समय में अच्छा उत्पादन होता है। इस प्रोसेस में पौधों को अलग-अलग जगह रखा जाता है। इस खेती में बीज के खराब होने की आशंका बहुत कम ही होती है। पूरा सिस्टम ऑटोमेटेड होता है, इसलिए कहीं से भी बैठकर इसे ऑपरेट कर सकते हैं।

22 हजार पौधे

ऋषभ बताते हैं कि फार्म में एक बार में अलग-अलग सब्जियों के 22 हजार पौधे लगाते हैं। एक बार में वे 15 से 20 तरह की सब्जियां उगा लेते हैं। इनके बीज हैदराबाद, पुणे और गुड़गांव से मंगवाते हैं।

ये सब्जियां

ऋषभ बताते हैं कि उनके वहां इटैलियन बेसिल, चेरी टमैटो, रेड स्विस चार्ड, बेबी पालक, ग्रीन ओरेंगेनो, लेट्यूस (अलग-अलग टाइप की), केल, सेलरी, सनफ्लॉवर, रोजमेरी, पास्ले सहित अन्य वैरायटी की सब्जियां उगाई जाती हैं।

हार्वेस्ट एक्सपीरिएंस

ऋषभ बताते हैं वे कस्टमर्स को अपने फार्म पर आकर अपने हाथों से सब्जी तोड़ने का मौका भी देते हैं। उनके फार्म पर ही सलाद खाने की सुविधा भी है। यहां 500 रुपए का चार्ज देकर लोग नेचर के बीच समय बिता सकते हैं। वहां मौजूद लोगों की देख-रेख में आप सब्जियां भी तोड़ सकते हैं।

80 फीसदी पानी की बचत

पूजा ने बताया कि इस तकनीक का फायदा यह है कि इसके लिए पानी की जरूरत बहुत कम होती है। सामान्य खेती के मुकाबले इसमें 20 प्रतिशत ही पानी की जरूरत होती है। साथ ही इसे ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम के जरिए ऑफिस में बैठकर भी पौधों की देखभाल की जा सकती है। इस सिस्टम के साथ ही बहुत अधिक स्पेस की अनिवार्यता भी खत्म हो जाती है। गर्मी में उन्हें 5 हजार लीटर पानी तीन से चार दिन में लगता है, जबकि सर्दी के दिनों में 5 हजार लीटर पानी हफ्तेभर तक चलता है।

घर की छत पर भी फार्म

पूजा ने बताया कि अब वे इंदौर में लोगों के घरों की छत पर भी मिनी फार्म तैयार कर सकते हैं। इसका खर्च 45 से 50 हजार रुपए आता है। अगर किसी को अपनी घर की छत पर ये सब्जियां उगाना है तो ये ऑप्शन भी आपको यहां मिल जाएगा।

शुरुआत से ही अच्छे प्लांट लगाए

ऋषभ के मुताबिक शुरुआत से ही हमने हाइड्रोपोनिक सिस्टम के जरिए फॉर्म पर ढेर सारे प्लांट लगाए। कुछ महीने बाद ही सब्जियां निकलने लगीं यानी शुरुआत में ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला। खास बात यह है कि हम इंदौर में प्रदेश के पहले ऐसे स्टार्टअप हैं जो कमर्शियल लेवल पर हाइड्रोपोनिक सिस्टम से खेती कर रहे हैं। इंदौर में कई लोग हैं जो इस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वह पर्सनल लेवल पर कर रहे हैं। इस तकनीक की सबसे खास बात यह है कि इससे 1 एकड़ जमीन पर 4 एकड़ जमीन के बराबर फसल लगाई जा सकती है।

पौष्टिक गुणों से भरपूर अंकुरित अनाज में छिपा है सेहत का राज

पल्लवी सिंह, पीएचडी शोध छात्रा

पारिवारिक संसाधन प्रबन्ध एवं उपभोक्ता विज्ञान विभाग

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या (उ.प्र.)

अंकुरित अनाज को स्प्राउट्स के नाम से जाना जाता है। ये अनाज या फलियों के अंकुरित बीज होते हैं, जिन्हें पौष्टिक आहार में शामिल किया गया है। प्राकृतिक चिकित्सा में अंकुरित अनाज को दवाओं के रूप में जाना जाता है, ये पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इनमें अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है ये ऐसे बीज होते हैं जिनसे छोटे- छोटे अंकुर निकलने शुरू हो जाते हैं। यह अंकुरण प्रक्रिया आमतौर पर कई घंटों तक अनाज या बीजों को भिगोने से शुरू होती है। अंकुरित अनाज में कई तरह के अनाज, फलियां, सब्जियों के बीज आदि प्रयोग किये जाते हैं।

सेम, मटर, बादाम, मूली के बीज, अल्फाल्फा के बीज, कद्दू के बीज, तिल के बीज, सूरजमुखी के बीज, ब्रसेल्स, मूंग दाल, चना, मेथी, सोयाबीन, क्विनोआ आदि को हम अंकुरित अनाज के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं। अंकुरित होने पर अनाज में पाया जाने वाला स्टार्च- ग्लूकोज, फ्रक्टोज और माल्टोज शर्करा में बदल जाता है। इससे न केवल अनाज का स्वाद बढ़ता है, बल्कि इसके पोषक तत्वों और पाचक गुणों में भी वृद्धि होती है। यही कारण है कि साबुत अनाज की तुलना में अंकुरित अनाज ज्यादा पौष्टिक माने जाते हैं।

अंकुरित अनाज में पाये जाने पोषक तत्व- अंकुरित अनाज में क्लोरोफिल, विटामिन ए, बी, सी, डी और के, भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जोकि कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटैशियम, मैगनीशियम, आयरन जैसे खनिजों लवणों का बेहतर स्त्रोत है। अंकुरित अनाज में फाइबर, फोलेट, ओमेगा- 3 फैटी एसिड भी पाया जाता है। इनमें खासतौर से विटामिन- सी, बी- कॉम्प्लेक्स, थायमिन, राइबोप्लेविन और नायसिन की मात्रा दोगुनी हो जाती है। अनाज को अंकुरित करने का तरीका- अंकुरित अनाज सबसे सस्ता और पौष्टिक आहार होता है। अनाज को , रात भर पानी में भिगोकर रख दें। अगले दिन उसे चार- पांच बार पानी से अच्छी तरह धो लें और किसी गीले कपड़े में अच्छी तरह से लपेट कर रख दें। ध्यान रहे कि कपड़े में नमी बरकार रहे, अगर ऐसा नहीं है तो समय- समय पर पानी का छिड़काव करते रहें। अगले दिन ही गीले किये गये अनाज अंकुरित हो जायेंगे। सर्दियों के मौसम की अपेक्षा गर्मी के मौसम में बीजों को अंकुरित करना ज्यादा आसान होता है। इस प्रक्रिया से आप प्रतिदिन अंकुरित आहार तैयार कर सकते हैं।

अंकुरित अनाज खाने के लाभ: अंकुरित अनाज हमारी सेहत के लिए बहुत लाभदायक होता है। इसका उपयोग हमें कई तरह की बीमारियों से बचाता है।

मोटापे के लिए अंकुरित अनाज: यदी आप अपना वजन कम करने का प्रयास कर रहे हैं, तो अपने आहार में अंकुरित आहार जरूर शामिल करें। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जिसे खाने के बाद पेट काफी देर तक भरा रहता है और हम अतिरिक्त कैलोरी लेने से बच जाते हैं। अंकुरित अनाज में कैलोरी की मात्रा बहुत ही कम होती है, इसीलिए यह वजन घटाने में कारगर साबित होता है।

स्टैमिना बढ़ाने के लिए: अंकुरित आहार ताकत का भंडार है। यही कारण है कि इसे सुबह के नाश्ते के अलावा कई लोग भोजन में भी नियमित तौर पर शामिल करते हैं, जिससे उनका स्टैमिना बना रहे।

आंखों के लिए लाभदायक: आंखों के लिए अंकुरित अनाज बहुत लाभदायक होते हैं। इसका सेवन करने से हमारी दृष्टि यानि कि देखने की क्षमता बेहतर होती है। आंखों से संबंधित रोगों से लड़ने के लिए अंकुरित अनाज लाभदायक साबित होते हैं।

बेहतर पाचन तंत्र: अंकुरित अनाज पाचन शक्ति बढ़ाने और उसे दुरस्त रखने का काम करते हैं। अंकुरण की प्रक्रिया के बाद अनाज में पाये जाने वाले कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन और भी ज्यादा पाचक व पौष्टिक हो जाते हैं। इससे आपका पाचन तंत्र भी सुचारु रूप से कार्य करता है।

इम्युनिटी पावर बढ़ाए: अंकुरित आहार को नियमित तौर पर लेने से रोगप्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है , तथा शरीर के हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में सहायता मिलती है।

डायबिटीज(मधुमेह) में फायदेमंद: कुछ अध्ययन बताते हैं कि अंकुरित अनाज कार्बोस की कुल मात्रा को कम करने में सहायता करते हैं, साथ ही इसमें एमिलेज एंजाइम होता है जोकि ग्लूकोज को तोड़ने और पचाने में मदद करता है। डायबिटीज (मधुमेह) में मेथी को अंकुरित करके खाना अधिक लाभदायक होता है।

त्वचा और बालों के लिए लाभकारी: अंकुरित अनाज में ढेरों विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, जोकि हमारी त्वचा और बालों को स्वस्थ रखने का काम करते हैं। स्प्राउट्स एक तरह से रक्त का शुद्धिकरण का काम करते हैं, जिससे हमारी त्वचा बेदाग और निखरी नजर आती है। इसके सेवन से हमारे बाल घने होते है और उनका झड़ना भी कम हो जाता है ।

दिल के रोगों के लिए रामबाण: अंकुरित अनाज का सेवन करना दिल के लिए अधिक लाभकारी होता है। जो लोग रोजाना अपने आहार में अंकुरित अनाज शामिल करते हैं, उन्हें अन्य लोगों की तुलना में दिल का दौरा पड़ने की आशंका बहुत कम होती है।अंकुरित अनाज में मौजूद पोषक तत्व आपके रक्त में उपस्थित हाई कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम कर देता है, जिससे दिल से संबंधित रोग होने की आंशका कम हो जाती है ।

कैंसर के लिए रामबाण: स्प्राउट्स में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रैडिकल्स को नष्ट करते हैं, ताकि त्वचा को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे और त्वचा कैंसर की आशंका खत्म हो जाती है।

गर्भवती महिलाओं के लिए: गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं को अंकुरित अनाज अपने आहार में शामिल करने का सुझाव दिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे नवजात शिशु की मानसिक और शारीरिक कमजोरियों को दूर करने में लाभ मिलता है। इसका उपयोग करने से शिशु के विकास में भी सहायता मिलती है।

भूजल संरक्षण: उत्तर भारत मे रोपाई धान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए

जल ऊर्जा का भंडार, पोषक तथा जीवनदाता है। इसके बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं और साथ ही पीने योग्य जल धरती पर अत्यल्प मात्रा में उपलब्ध है। ऐसे में दुनियाभर में जल बचाने की कोशिशें जारी हैं। विश्व स्तर पर जन जागरूकता अभियान जारी है। जल संरक्षण एक नागरिक के तौर पर भी हमारा दायित्व है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51ए (7) के मुताबिक, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है- वनों, झीलों, नदियों, भूजल और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना। केन्द्रीय भूजल बोर्ड व जल आयोग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार देश की खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण सघन कृषि क्षेत्र वाले उत्तरी राज्यो पंजाब-हरियाणा मे पिछले 50 वर्षो से लगातार धान-गेहूं फसल चक्र अपनाने के कारण भूजल स्तर आधा मीटर प्रतिवर्ष गिरने से इन राज्यो के आधे से ज्यादा ब्लॉक गंभीर भूजल संकट मे आ चुके है।

विरेन्द्र सिंह लाठर

भूजल संकट को रोकने के लिए वर्ष 2009 में हरियाणा और पंजाब प्रिर्वेशन आफ सबसायल वाटर एक्ट बनाए, जिसमें 15 जुन से पहले धान फसल की रोपाई पर प्रतिबन्ध लगाया गया, लेकिन इन सब सरकारी प्रयासों के बावजूद अभी तक जल संरक्षण खासतौर पर भूजल संरक्षण के प्रयास निरर्थक साबित हुए हैं।

धान रोपाई भूजल बर्बादी के लिए मुख्यतया दोषी: यह सर्वविदित है कि 1970 तक उत्तर भारत मे शिवालिक हिमालय के साथ लगते मैदानी खादर व तराई क्षेत्रों मे भूजल भूमि सतह के बिल्कुल नजदीक था, लेकिन हरित क्रांति दौर की सघन कृषि तकनीक विशेष तौर पर रोपाई धान, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण आदि से भूजल का अंधाधुंध दोहन होने से गंभीर भूजल संकट बनता जा रहा है, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन उपयोगी जल की उपलब्धता पर भी सवाल खड़ा हो रहा है।

आदिकाल से सभी अनाज, दलहन , तिलहन आदि फसलों की खेती के लिए, वत्तर खेत को तैयार करके बीज की सीधी बुआई प्रचालित तकनीक रही है। वर्ष-1966 से पहले, संयुक्त पंजाब और उत्तर भारत में भी किसान सीधी बुआई से ही धान की खेती किया करते थे। तब धान का क्षेत्रफल कम होने व सस्ते मजदूर मिलने से निराई-गुड़ाई से खरपतवार नियंत्रण किया जाता था।

लेकिन सरकार ने हरित क्रांति दौर में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, अंतराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान-मनीला से धान की उन्नत बौनी किस्मों के साथ, भूजल बर्बादी वाली खड़े पानी वाली रोपाई धान तकनीक आयात करके उत्तर भारतीय किसानों पर थोप दी। इससे धान की पैदावार तो जरूर बढ़ी, लेकिन खेती लागत मे भी कई गुणा बढोतरी और भूजल की भयंकर बर्बादी हुई, जिससे जम्मू से पटना तक सतलुज, यमुना, गंगा नदियों के मैदानी क्षेत्रो में भूजल डार्क जोन मे चला गया। धान रोपाई से भयंकर भूजल बर्बादी को रोकने के लिए जहां कृषि वैज्ञानिकों ने इस सदी की शुरुआत में सूखे खेत में धान की सीधी बुआई तकनीक को प्रसारित किया, जिसे किसानों ने पूरी तरह से नकार दिया, क्योंकि इस पद्धति में सिंचाई पानी की बचत नहीं होने और फसल बुआई के तुरंत बाद सिंचाई और फिर हर तीन दिन बाद सिंचाई लगाने से फसल मे खरपतवार की बहुतायत होने से किसान परेशान हो गए।

दूसरी और सरकार ने तकनीकी तौर पर अव्यावहारिक योजनायों (धान छोड़े मक्की बोये, धान खेत खाली रखने वाले किसान को 7000 रुपए/एकड़ प्रोत्साहन राशि, सुक्षम सिंचाई, फसल विविधिकरण आदि) से किसानों को भ्रमित किया।

तर-वत्तर सीधी बिजाई धान-भूजल बर्बादी रोकने का समाधान: वश्व खाद्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 150 दिन की धान फसल को मात्र 500-700 मिलीलीटर सिंचाई जल की आवश्यकता होती है। जिसमें आधे से ज्यादा सिंचाई जल की पूर्ति मॉनसून वर्षा करती है। लेकिन हरित क्रांति दौर में सरकार द्वारा अनुशंसित भूजल बर्बादी वाली रोपाई धान तकनीक में 1500-2000 मि.ली. सिंचाई जल की जरूरत होती है।

इससे खेती लागत मे बढ़ोतरी और ऊर्जा-भूजल संसाधनों की भारी बर्बादी हुई। जिसे रोकने के लिए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान-क्षेत्रीय केन्द्र करनाल की हमारी टीम ने वर्ष-2014-15 मे तर-वत्तर सीधी बिजाई धान तकनीक को विकसित करके किसानों मे प्रसारित किया, जिससे खरपतवार नियंत्रण आसान हुआ और पैदावार रोपाई धान के बराबर ही मिलने लगी।

इसके असर से कोरोना आपदा काल वर्ष-2021 में प्रवासी मजदूरों की भारी कमी से पंजाब में किसानो ने लगभग 6 लाख हेक्टेयर यानि कुल धान क्षेत्र के 20 प्रतिशत क्षेत्र में तर-वत्तर सीधी बुआई तकनीक से धान फसल सफलता से उगाई और प्रदेश में रिकार्ड 12.78 मिलियन टन धान का उत्पादन हुआ। इसी तरह हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा 1अप्रैल 2023 को दी गई जानकारी के अनुसार खरीफ-2022 में हरियाणा में किसानों ने 72,000 एकड़ से ज्यादा भूमि पर सीधी बिजाई धान तकनीक को सफलतापूर्वक अपनाकर 31,500 करोड लीटर यानि लगभग 40 लाख लीटर /एकड़ भूजल की बचत की। इसके लिए सरकार ने लगभग 30 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि किसानों को बांटी। अब हरियाणा सरकार द्वारा भूजल संरक्षण के इन प्रयासों को गति देने के लिए, भूजल बर्बादी वाली रोपाई धान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर सीधी बिजाई धान पद्धति को 7,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन देना चाहिए।

बादलों में पनप रहा संकट, मानव जीवन के लिए बेहद ही खतरनाक: रिसर्च

वैज्ञानिकों का दावा है कि पृथ्वी के ऊपर मडराने वाले बादलों में संकट पनप रहा है, जोकि मानव जीवन के लिए बेहद ही खतरनाक है। हाल ही में नीदरलैंड की एक साइंस पत्रिका जर्नल साइंस ऑफ द टोटल एनवायरमेंट में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, जिसमे बताया गया कि बादलों पर रिसर्च करने वालें वैज्ञानिकों को बादलों में एक सबसे खतरनाक बैक्टेरिया मिला है। जोकि बेहद ही खतरनाक है। रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि रिसर्च में वैज्ञानिकों ने विभिन्न ऊंचाइयों पर मौजूद बादलों के सेंपल लिए और उनमें मौजूद बैक्टीरिया की जांच की। उन्होंने बताया कि ये बैक्टीरिया प्रकृति में पाए जाने वाले बैक्टीरिया से बिल्कुल अलग है, और इनका नाम बैक्टीरिया एयरोसोल एसिडोफिलिस है। ये बैक्टीरिया सामान्यतया बादलों के साथ अधिक मात्रा में ऊपर जा सकते हैं।

एसिडिक माहौल में भी रह सकते हैं जीवित: रिसर्च में बताया गया कि ये बैक्टीरियों एक खास वजह से एसिडिक माहौल में भी जीवित रह सकते हैं, जिसके कारण इनपर किसी भी दवा या एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होता है। इस वजह से ये बैक्टीरियों और भी खतरनाक बताएं जा रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बैक्टीरिया से मानव के अंग-प्रत्यंगों में संक्रमण फैलने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। बादलों के अंदर भी रह सकते है। एक पत्रिका में प्रकाशित रिपोर्ट में बताया गया कि वैज्ञानिकों में इन बैक्टीरियों का पता लगाने के लिए एयर सैंपलिंग टूल का इस्तेमाल किया था, जोकि बादलों से सैंपल लेने में सक्षम है। इस दौरान सैंपलों के अलग-अलग ऊंचाइयों पर बैक्टीरिया की जांच करते हुए पाया गया कि ये बैक्टीरिया बादलों के साथ लंबी दूरी तक तय कर सकते हैं, और इन्हें हवा के द्वारा भी फैलाया जा सकता है। इन बैक्टीरियों के पोषण के लिए सूर्य की रश्मि की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे ये बादलों के अंदर भी तंदुरुस्त रह सकते हैं। इस रिसर्च को करने के लिए सेंट्रल फ्रांस के एक एटमॉस्फेरिक रिसर्च स्टेशन से बादलों के सैंपल को जमा किया गया था। जमा किए गए सैंपलों का अध्ययन करने के बाद, रिसर्चरों ने पाया कि प्रति मिलीमीटर क्लाउड वॉटर में 300 से 30,000 तक बैक्टीरिया होते हैं।

एंटिबायोटिक के खिलाफ प्रतिरोध कर सकते हैं विकसित: रिसर्च में एक चौकाने वाला तथ्य भी सामने आया है, रिसर्च में पाया गया कि इन बैक्टीरिया में से 29 अलग-अलग सबटाइप में एंटिबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स मिले जोकि जीवाणुओं के अधिकांश प्रकारों के लिए अनुसंधान एवं उपचार में इस्तेमाल किए जाने वाले एंटिबायोटिक के खिलाफ प्रतिरोध विकसित कर सकते हैं। इस रिसर्च से यह भी पता चला है कि बादलों में बहुत से ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें कोई एंटिबायोटिक का असर नहीं होता। यह बैक्टीरिया बादलों के सहारे लंबी दूरी तय करते हैं और इस तरह से बादलों को आकार बढ़ाने में मदद भी करते हैं। इस रिसर्च से ये भी सामने आया है कि इन बैक्टीरियों का जीवनकाल बादलों की तुलना में बहुत लंबा होता है।

श्योपुर में 28 गेहूं खरीदी केंद्रों पर 5955 किसानों से खरीदा 72965 मैट्रिक टन गेहूं

गेहूं खरीदी में श्योपुर संभाग में अव्वल, मुरैना फिसड्डी

शिवपुरी/श्योपुर। खेमराज मौर्य

समर्थन मूल्य पर शुरू हुई गेहूं की खरीदी शुरूआत में तो धीमी रही। लेकिन अब समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी में तेजी आ गई है। अब जिले के किसानों ने समर्थन मूल्य को अपना इतना अधिक समर्थन दे दिया कि श्योपुर गेहूं खरीदी के मामले में ग्वालियर-चंबल संभाग में पहले स्थान पर पहुंच गया है। श्योपुर में 5955 किसानों से 72965 मैट्रिन गेहूं की खरीदी की गई है। चूंकि अभी गेहूं की खरीदी 10 मई तक होना है, इसलिए श्योपुर जिले में गेहूं की खरीदी और बढ़ने की उम्मीद है। जबकि दूसरे स्थान पर शिवपुरी जिला है। जहां एक हजार 889 किसानों से 15 हजार 886 मैट्रिक गेहूं खरीदा गया है।

उधर, मुरैना पूरे संभाग में फिसड्डी बना हुआ है। क्योंकि मुरैना में अभी एक भी किसान ने अपना गेहूं समर्थन मूल्य पर नहीं बेचा है। गौरतलब है कि जब समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी शुरू हुई, तब मंडी में गेहूं का भाव समर्थन मूल्य से ज्यादा था, इसलिए जिले के किसानों ने खरीदी केन्द्रों की तरफ मुंह भी नहीं किया था। ज्यादातर किसानों ने मंडी में पहुंचकर अपना गेहूं सीधे व्यापारियों को विक्रय किया। जिसके चलते श्योपुर जिले में बनाए गए 33 गेहूं खरीद केन्द्र सूने ही पड़े रहे। लेकिन अब मंडी में गेहूं का भाव कम हो गया है और चमक विहीन गेहूं को मंडी में व्यापारी भी नहीं खरीद रहे हैं।

जबकि सरकार ने चमक विहीन गेहूं को समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने का एलान कर दिया था। इसलिए किसानों ने समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने में रुचि लेना शुरू कर दिया है। किसानों की रुचि इतनी अधिक बढ़ी कि जिले के 28 खरीद केन्द्रों पर 72665.11 मैट्रिक टन गेहूं की खरीदी हो गई। जबकि पिछले साल महज पांच किसानों के द्वारा ही समर्थन मूल्य पर अपना गेहूं बेचा था।

श्योपुर के पांच, मुरैना के 28 केन्द्रों पर सन्नाटा, नहीं खरीदा एक भी दाना

भले ही गेहूं खरीदी के मामले में श्योपुर जिला संभाग में अव्वल स्थान पर बना हुआ है। लेकिन 33 गेहूं खरीदी केन्द्रों में से 5 खरीदी केन्द्र ऐसे है, जिन पर सन्नाटा पसरा हुआ है। यहां अभी एक भी दाना खरीदी नहीं गया है। ये केन्द्र विजयपुर क्षेत्र है। जबकि मुरैना के 28 खरीदी केन्द्र भी सूने पड़े है। यहां भी कोई किसान गेहूं लेकर विक्रय के लिए नहीं पहुंचा है। जिसकारण मुरैना जिला फिसड्डी रह गया है।

चना खरीदी में दतिया, सरसों में भिंड टॉप पर। गेहूं खरीदी के मामले में भलेही दतिया और भिंड संभाग में क्रमशः पांचवें और छटवें स्थान पर बने हैं, लेकिन चना खरीदी में दतिया और सरसों खरीदी में भिंड पूरे संभाग में टॉप पर है। बताया गया है कि चना खरीदी के दौरान दतिया जिले में 13 खरीद केन्द्रों पर 1490 किसानों से 5341.82 मैट्रिक टन चना खरीदा गया है, जबकि सरसों खरीदी में भिंड जिले में 16 खरीदी केन्द्रों पर 2749 किसानों से 13816.30 एमटी सरसों खरीदी गई है। इन दोनों जिलों से ज्यादा चने और सरसों की खरीदी संभाग के दूसरे जिले में नहीं हुई है।

जिलों में गेहूं की खरीदी

जिला	किसान	गेहूं खरीदी
श्योपुर	5955	72965.11
शिवपुरी	1869	15886.21
गुना	1794	15693.74
अशोकनगर	1053	9805.62
दतिया	862	6329.82
भिंड	670	6058.60
ग्वालियर	358	3764.05
मुरैना	00	00
कुल	12561	130503.15

नोट-गेहूं खरीदी मैट्रिक टन में।

चना और सरसों खरीदी

जिला	चना	सरसों
दतिया	5341.82	167.50
अशोकनगर	1970.85	4376.11
श्योपुर	1656.32	4150.90
गुना	1644.15	2191.65
शिवपुरी	509.10	2033.90
भिंड	257.85	13816.30
ग्वालियर	241.85	6747.80
मुरैना	00	10617.89

नोट : यह आंकडे 9 मई तक के हैं।

केंद्रीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में हुई शंघाई सहयोग संगठन देशों के कृषि मंत्रियों की 8वीं बैठक

प्रधानमंत्री का जोर टेक्नोलॉजी के जरिए कृषि के समग्र विकास पर: तोमर

भोपाल। जागत गांव हमार

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों के कृषि मंत्रियों की 8वीं बैठक बीते सप्ताह केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई। इसमें भारत सहित रूस, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, चीन एवं पाकिस्तान ने भाग लिया। इसमें भारत की अध्यक्षता में, एससीओ के सदस्य देशों ने स्मार्ट कृषि परियोजना को अंगीकृत किया। तोमर ने स्मार्ट कृषि कार्ययोजना और कृषि में नवाचार की पहल पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर देश में टेक्नालाजी के माध्यम से कृषि के समग्र विकास पर है और इसी दिशा में स्मार्ट एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए भारत ने अनेक ठोस कदम उठाए हैं। केंद्रीय मंत्री तोमर ने भारत की ओर से एससीओ की बैठक में सभी का स्वागत करते हुए कहा कि भारत बहुपक्षीय, राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक व जन-जन के बीच इंटरेक्शन को बढ़ावा देने में एससीओ के साथ अपने संबंधों को महत्व देता है। एससीओं के कृषि मंत्रियों की बैठक आयोजित करना, विशेष रूप से वर्तमान स्थिति में खाद्य सुरक्षा व पोषण में सहयोग सुदृढ़ करने पर चर्चा करना हमारे लिए प्रसन्नता व गर्व की बात है। तोमर ने कहा कि वर्तमान स्थितियों में खाद्य आपूर्ति श्रृंखला की सामान्य कार्यपद्धति बनाए रखने के लिए खाद्य व पोषण सुरक्षा के लिए विभिन देशों के बीच घनिष्ठ संपर्क व सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत, कृषि क्षेत्र में वैश्विनक स्तर पर सबसे बड़ा नियोक्ता है, जहां हमारी आधी से अधिक आबादी कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों से जुड़ी हुई है, वहीं भारत, अनेक देशों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियों का प्रतिनिधित्व भी करता है। इसका महत्व इससे भी जाहिर होता है कि भारत में वर्ष 2013-14 से 10 साल में कृषि व संबद्ध क्षेत्रों के बजट आवंटन में 5 गुना से ज्यादा वृद्धि हुई है। गत वर्षों के दौरान भारत ने कृषि क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया, खाद्यान्न उत्पादन के साथ वैश्विक खाद्य सुरक्षा में योगदान देते हुए निर्यात में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की और कृषि एवं संबद्ध उत्पादों का निर्यात 4 लाख करोड़ के पार हो गया।

ताकि आत्मनिर्भर और खाद्य सुरक्षित राष्ट्र बन सकें

भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली व किसानों के लिए मूल्य समर्थन प्रणाली विश्व में अद्वितीय है। यह हमारे नीति-निर्माताओं की दूरदर्शिता, कृषि वैज्ञानिकों की कुशलता एवं किसानों के अथक परिश्रम का ही सदपरिणाम है कि आज भारत खाद्यान्न मामले में आत्मनिर्भर है। अनाज, फल, सब्जियां, दूध, अंडे, मछली जैसी कई वस्तुओं का अग्रणी उत्पादक है। उन्होंने कहा कि किसानों का कल्याण एवं कृषि क्षेत्र का समग्र विकास भारत सरकार की उच्च प्राथमिकता रही है। भारत, कृषि क्षेत्र में अपने व्यापक विकास पथ के साथ, द्विपक्षीय रूप से, साथ ही अंतरराष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से अन्य देशों को अपनी सर्वोत्तम पद्धतियां साझा करना एवं क्षमताओं का निर्माण करना जारी रखेगा, ताकि वे भी आत्मनिर्भर एवं खाद्य सुरक्षित राष्ट्र बन सकें। समृद्ध कृषि अनुसंधान ने खाद्य सुरक्षा मामले का समाधान करने, किसानों-कृषि श्रमिकों की आय में सुधार करने के साथ लोगों के भरण-पोषण के लिए अहम भूमिका निभाई है।

पीएम का कुशल नेतृत्व जैविक खेती व प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा दे रहा

तोमर ने पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम पर कहा कि इसके तहत देशभर में करोड़ों किसानों को प्रति वर्ष 6 हजार रुपए दिए जा रहे हैं और किसानों के बैंक खातों में अब तक करीब 2.40 लाख करोड़ जमा कराए जा चुके हैं। किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने एवं इनके जरिये सभी पीएम-किसान लाभार्थियों को कवर करने पर ध्यान देने के साथ करोड़ों किसानों को रियायती संस्थागत ऋण प्रदान किया गया है। पीएम के नेतृत्व में भारत सतत् उत्पादकता, खाद्य सुरक्षा व मृदा स्वास्थ्य पर जोर देने के साथ जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा दे रहा है। किसानों को, किसान समूहों में जोड़कर उनकी आर्थिक क्षमता बढ़ाने के लिए 10 हजार नए एफपीओ के गठन की योजना शुरू की गई।

कृषक महिलाओं, को सशक्त बनाने के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया जा रहा

पीएम फसल बीमा योजना से किसानों बीमा कवर प्रदान किया जा रहा है। जिसके तहत प्राकृतिक प्रकोप से नुकसान की भरपाई में 1.30 लाख करोड़ दिए गए हैं। किसानों की बाजार तक पहुंच बढ़ाने इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार विकसित किया गया है। किसानों की आय बढ़ाने के लक्ष्य के साथ भारत ने सिंचाई की नई अवसंरचनाएं बनाने, उर्वरकों के संतुलित उपयोग सहित मृदा उर्वरता का संरक्षण करने, खेत से बाजार तक कनेक्टिविटी देने, आईसीटी लिंकेज आदि के लिए भी कार्यक्रम शुरू किए हैं। नई प्रौद्योगिकियां व पद्धतियां विकसित करके बड़े पैमाने पर लैब-टू-लैंड पहल कर किसानों, कृषक महिलाओं, को सशक्त बनाने के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया जा रहा है।

भू-जलस्तर को खतरा

आगामी दिनों में और नीचे गिर सकता है भूजल स्तर, लोग बोले-ग्रीष्मकालीन धान की फसल पर रोक लगाने की जरूरत

पहली बार 150 हेक्टेयर में ग्रीष्मकालीन धान की फसल उगाई और जमीन के अंदर से पानी खींचकर होगी सिंचाई

भोपाल। जागत गांव हमार

यूं तो प्रदेश के श्योपुर में ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती होती है, लेकिन इस बार जिले के किसानों ने मूंग की फसल के साथही पहली बार 150 हेक्टेयर में ग्रीष्मकालीन धान की उगा ली है। अब धान की इस फसल की सिंचाई जिले के किसान भरी गर्मी में जमीन के नीचे पानी निकालकर कर रहे हैं, जो भूजल स्तर के लिए खतरा है। क्योंकि पानी के दोहन से भूजल स्तर में और गिरावट आना तय लग रहा है। इसको लेकर जिले के लोगों ने चिंता व्यक्त करते हुए प्रशासन ने ग्रीष्मकालीन धान की फसल पर रोक लगाए जाने की जरूरत बताई है।

उल्लेखित है कि, पहले श्योपुर में सरसों, सोयाबीन की फसल ज्यादा होती थी, लेकिन धीरे-धीरे किसान पंजाब की तर्ज पर धान करने लगे। यही वजह है कि साल दर साल धान का रकबा बढ़ता गया। यही वजह है कि, इस साल धान की रकबा 1 लाख से अधिक पहुंच गया था। धान की फसल में अच्छा मुनाफा होने की वजह से अब किसान गर्मी में इस फसल को करने लगे हैं। यही वजह है कि इस बार जिले के किसानों ने 150 हेक्टेयर में ग्रीष्मकालीन धान की फसल रोप दी है। जिसकी सिंचाई अब ट्यूबवेलों के पानी से होगी। चूंकि धान के लिए पानी की जरूरत ज्यादा होती है,इसलिए भू जल स्तर में गर्मी के मौसम में गिरावट होना ज्यादा लग रही है। क्योंकि इस समय जिले का औसत भू जल स्तर 63 मीटर नीचे पहुंच गया है। जागरूक लोगों का कहना है कि गर्मी के धान की पैदावार नहीं रोकी गई तो आने वाले समय में जल का बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। प्रशासन और कृषि विभाग को इस संबंध में किसानों को जागने की जरूरत है।

एक किलो धान पैदा करने में चार हजार लीटर पानी

गर्मी के मौसम में धान की खेती के लिए काफी मात्रा में पानी की जरूरत होती है। जानकारों की माने एक किलो धान पैदा करने में लगभग चार हजार लीटर पानी की खपत होती है। जिन इलाकों में गर्मी के धान की खेती की जा रही है, वहां भू-जल संकट तुलनात्मक रूप से अधिक है। जिले के कुछ क्षेत्रों को क्रिटिकल जोन में माना है। वहीं इन्हीं क्षेत्रों में ग्रीष्म कालीन धान की फसल लेने से भू-जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है।

3 हजार में मूंग तो 60 हेक्टेयर में उड़द की फसल

गर्मी के मौसम में किसानों के द्वारा मूंग की फसल करने का दायरा भी बढता जा रहा है। पिछले साल जिले में 2500 हेक्टेयर में मूंग की फसल उगाई गई थी, लेकिन इस साल 3 हजार हेक्टेयर में मूंग की फसल उगाई गई है। जबकि 60 हेक्टेयर में उडद की फसल लगाई गई है। किसानों का कहना है कि इन फसलों में पानी की जरूरत ज्यादा नहीं होती है, इसलिए इन फसलों को करने से भूजल स्तर के ज्यादा गिरने की आशंका नहीं रहती है।

- धान की फसल में सिंचाई के लिए पानी की जरूरत ज्यादा होती है। ऐसे में किसान ग्रीष्मकालीन धान की फसल करेंगे तो उससे भू जल स्तर में गिरावट आना तय है। किसानों को इस दिशा में जागरूकता लानी चाहिए और ऐसी फसलों का चयन करना चाहिए,जिसमें पानी की जरूरत कम हो।

केएम गुप्ता, एसडीओ पीएचई, श्योपुर

- इस बार जिले में किसानों के द्वारा 150 हेक्टेयर में ग्रीष्मकालीन धान की बुवाई की गई है। हम इस संबंध में किसानों को समझा सकते है,उन्हें रोक नहीं सकते।

पी गुजरे, उप संचालक, कृषि श्योपुर

- किसान भाइयों द्वारा गर्मियों में ली जा रही धान की फसल भविष्य में जल संकट पैदा कर सकती है। खरीफ सीजन में की जाने वाली फसल में रोग एवं कीटों के प्रकोप की भी अत्यधिक संभावना रहती है।

डॉ. एलएस गुर्जर, कृषि विज्ञानिक, बड़ौदा

- जिले में पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं है इसलिए गर्मी के सीजन में किसान भाइयों को धान की फसल नहीं करना चाहिए, क्योंकि धान की फसल करने से भू-जल स्तर नीचे चला जाएगा। जिसके कारण पीने के पानी की समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। गर्मियों के सीजन में धान की फसल की अपेक्षा ऐसी फसल करना चाहिए जिसमें पानी का कम से कम उपयोग हो।

भरत सिंह जाट, किसान नेता, श्योपुर

- धान की फसल के लिए बरसात का सीजन ही उचित माना गया है। क्योंकि इस फसल की सिंचाई के पानी की सबसे ज्यादा आवश्कता पड़ती है। धान खेत में 24 घंटे पानी भरे रखना पड़ता है। अगर किसान गर्मियों में धान की फसल करेंगे तो जिले का वाटरलेवल काफी नीचे गिर जाएगा। ऐसे में पेयजल संकट का भी लोगों का सामना करना पड़ेगा।

नाथूलाल मीणा, किसान, नेता श्योपुर

-प्रमुख प्रजातियां: नरेंद्र बेल 5, नरेंद्र बेल 7, सीआई एसएचबी, पूसा उर्वशी

बेल की बगवानी लाभकारी और औषधीय गुणों से भरपूर

आजमगढ़। जागत गांव हमार

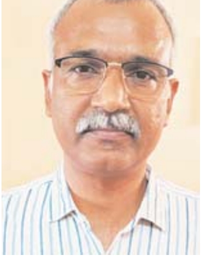

बेल एक ऐसा फल है जो अपने में लाखों फायदे छुपाए हुए है। बेल का सभी भाग छाल, पत्ती और फल औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसका इस्तेमाल धार्मिक तौर के साथ साथ आयुर्वेदिक दवाओं में खूब किया जाता है। कब्ज की समस्या से परेशान लोगों को बेल और बेल का जूस काफी लाभदायक होता है। बेल में विटामिन ए, बी, सी, खनिज तत्व, कार्बोहाइड्रेट समेत कई अन्य औषधीय गुणों होते हैं। बेल की मधुमेह रोगियों के लिए औषधि है। पत्तियों में टैनिन, लौह, कैल्शियम, पोटैशियम और मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। इसका शर्बत कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करता है। बेल की अच्छी पैदावार के लिए आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या के अधीन संचालित कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा आजमगढ़ के प्रभारी अधिकारी प्रोफेसर डीके सिंह ने बताया कि बेल की खेती कर किसान अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। डॉ. विजय कुमार विमल वैज्ञानिक उद्यान द्वारा बताया गया कि इसके लिए उपजाऊ मिट्टी उपयुक्त होती है। बेल बीज एवं कलम विधि दोनों तरह लगाया जाता है।

पौधे लगाने का समय जुलाई-अगस्त उपयुक्त

बेल की प्रजातियों की बात करें तो नरेंद्र बेल 5, नरेंद्र बेल 7, सीआई एसएचबी, पूसा उर्वशी आदि प्रमुख हैं। बेल को लगाने के लिए जुलाई से अगस्त महीना उचित होता है। बेल के कलमी पौधे 4 साल में फल देते हैं जबकि बीजू पौधे 6 से 7 साल में फल देते हैं। पौधों के लगाने के लिए 25 किग्रा सड़ी गोबर की खाद 50 ग्राम नाइट्रोजन, 50 ग्राम पोटाश, 25 ग्राम फास्फोरस युक्त उर्वरक से गड्ढे को भर दें फिर पौधे को लगाने के बाद सिंचाई कर दें। बेल के फलों को गिरने से बचाने एवं आंतरिक विगलन से बचाने के लिए 50 से 100 ग्राम बोरेक्स प्रति पौधा प्रयोग करना चाहिए। फल जब छोटे हों तो एक प्रतिशत बोरेक्स का छिड़काव दो बार 15 दिन के अंतराल कराना चाहिए।

फल पीले होने पर करें तोड़ाई

फलों को गिरने से बचाने के लिए प्लेनोफिक्स (हार्मोन) की एक मिली को चार लीटर पानी में डालकर छिड़काव करना चाहिए। पत्तियों पर होने वाले काले धब्बे के लिए बाविस्टिन का छिड़काव करें। बेल के पर्ण सुरंगी एवं पर्ण भक्षी इल्ली नामक कीट पत्तियों को काटकर नुकसान पहुचाती हैं। इससे बचाव के लिए प्रोफेनोफास एवं साइपरमैथ्रिन की 0.5 मिली दवा को 1 लीटर पानी में डाल कर दो तीन सप्ताह के अन्तराल पर छिड़काव करें। अप्रैल-मई के महीने में जब फलों का रंग हरे रंग से बदल कर पीले रंग का होने लगे तो फल तोड़ने योग्य हो जाता है। एक 10 से 15 वर्ष पूर्ण विकसित बेल से 80 से 100 फल प्राप्त हो जाता है।

25 सालों की मेहनत अब धीरे-धीरे रंग दिखाने लगी

काले मोतियों की उजली कहानी, बस्तर के जंगलों की जुबानी

डॉ.शशिकांत सिंह। बस्तर

काले मोतियों की खेती कोंडागांव में धीरे-धीरे परवान चढ़ रही है। लगभग 25 साल पहले यहाँ के एक प्रगतिशील किसान वैज्ञानिक डॉ. राजाराम त्रिपाठी ने खेती के जो जैविक एवं हर्बल खेती के जो नए नए प्रयोग शुरू किए थे। उनमें सबसे प्रमुख सपना था छत्तीसगढ़ के लिए काली-मिर्च की नई प्रजाति का विकास तथा उसे छत्तीसगढ़ के किसानों के खेतों पर और जंगलों में सफल करके दिखाना। डॉ. त्रिपाठी की 25 सालों की मेहनत अब धीरे-धीरे रंग दिखाने लगी है। आज क्षेत्र के सैकड़ों छोटे-छोटे आदिवासी किसान अपने घरों की बाड़ियों में खड़े पेड़ों पर काली मिर्च उगा रहे हैं और थोड़ा बहुत ही सही पर नियमित अतिरिक्त कमाई करने में सफल हुए हैं। इधर दूसरी तरफ सफलता की एक नई इबारत बस्तर के जंगलों में भी लिखी जा रही है। दरअसल, कुछ समय पूर्व डॉ.राजाराम त्रिपाठी, मां दंतेश्वरी हर्बल फार्म तथा रिसर्च सेंटर इनकी सहयोगी समाज सेवी संस्था संपदा ने प्रशासन तथा वन विभाग के सहयोग व मार्गदर्शन में आसपास की कुछेक वन क्षेत्रों में भी प्रायोगिक रूप से साल के पेड़ों पर तथा अन्य प्रजाति के पेड़ों पर भी मां दंतेश्वरी हर्बल समूह द्वारा विकसित काली मिर्च की नई प्रजाति के पौधे लगाए गए थे।

अतिरिक्त लाभांश मिलेगा

आज काली मिर्च की उन लताओं में फल आने लगे हैं। गर्मी की छुट्टियों के कारण घर में खाली बैठे बच्चों ने निकट की जंगलों में पड़े उस काली मिर्च को इकट्ठा किया और लाकर आगे विपणन के लिए मां दंतेश्वरी हर्बल समूह में जमा किया बच्चों द्वारा जेब खर्च के लिए इकट्ठा किए गए। इस काली मिर्च के उन्हें मां दंतेश्वरी हर्बल समूह से 4000 चार हजार रुपए का तत्काल भूगतान मिल गया हैं। इतना ही नहीं, यह काली मिर्च मां दंतेश्वरी हर्बल समूह के अन्य सदस्यों की काली मिर्च के साथ आगे अगर ज्यादा कीमत पर बिकेगी तो इन्हें नन्हे संग्रहकर्ताओं को भी इसका अतिरिक्त लाभांश मिलेगा। इसके लिए इन लोगों का नाम पता फोन नंबर आदि दर्ज कर लिए गया है।

पेड़ों को काटने से परहेज करेंगे

बच्चों का और उनके परिवार वालों का दोनों का उत्साह बढ़ा है। बच्चों के साथ आए उनके परिजनों का कहना था कि बच्चों के द्वारा खेल खेल में इकट्ठा किए गए इस काली मिर्च से बच्चों के आने वाले साल की पढ़ाई, की किताबों और नए कपड़ों के खर्चे की व्यवस्था हो गई है। इससे बच्चे और उनके मां-बाप सभी बहुत खुश हैं। जाहिर है इससे बच्चों को और अधिक काली मिर्च इकट्ठा करने की प्रेरणा मिलेगी और अब गांव के लोग भी ये हर साल अतिरिक्त आमदनी देने वाली काली मिर्च की लताएं जिन पेड़ों पर चढ़ी हैं। उन पेड़ों को काटने से परहेज करेंगे और शायद इससे बस्तर छत्तीसगढ़ का जंगल भी बच जाए।

-नई प्रजाति की उपज क्षमता 55 से 64 क्विंटल प्रति हेक्टेयर

बीएचयू में विकसित की गई नई प्रजाति की मालवीय मनीला सिंचित धान-वन

» यूपी सरकार ने दी तीन साल के लिए पूरे राज्य में परीक्षण की अनुमति

» वैज्ञानिकों का दावा-रोपाई के 115 से 120 दिन में पककर हो जाएगी तैयार

वाराणसी। जागत गांव हमार

वाराणसी के इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सहयोग से विकसित धान की नई किस्म को पूरे भारत में लॉन्च कर दिया गया है। इस धान के बीज को तैयार करने में बीएचयू के वैज्ञानिकों को 15 साल लगा है। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की प्रजाति पहचान समिति ने अपने 98 वें वार्षिक धान समूह बैठक में इस वैरायटी को प्रस्तुत किया गया। इस धान की लांचिंग आसाम कृषि विश्वविद्यालय जोरहट में की गई है। किसानों को इस धान को लगाने का फायदा यह है कि यह कई प्रमुख रोगों और कीट पतंगों के लिए प्रतिरोधी और सहनशील है। जैसे

लीफ स्पॉट, ब्राउन स्पॉट, बैक्टीरियल लीफब्लाइट, स्टेम बोरर, लीफ फोल्डर, ब्राउन प्लांट हापर, गालमिज इत्यादि। इस किस्म का कम दिन में तैयार होकर अधिक उपज क्षमता, पतला और लंबा दाना, अधिक मूल्य दिलाने वाला चावल और अन्य अच्छे गुणों के कारण उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा के किसानों की लागत कम और आमदनी बढ़ाने में सहयोगी हो सकता है।

यह बहुत जल्दी पकने वाली किस्म है। इसके पौधे की लम्बाई 102 से 110 सेंटीमीटर रहती है। रोपाई की अवस्था में 115 से 120 में पक कर तैयार हो जाता है। उपज क्षमता की बात करे तो 55 से 64 हेक्टेयर प्रति क्विंटल रहती है। इसकी खड़ा चावल निकलने का प्रतिशत 79.90 फीसदी, 68.50 प्रतिशत और 63.50 फीसदी है। इसके चावल की लंबाई 7.0 मिमी और मोटाई 2.1 मिमी है। यह एक लम्बा और पतले दाने का चावल है।
प्रो. श्रवण सिंह, कृषि वैज्ञानिक, बीएचयू

अखिल भारतीय स्तर पर परीक्षण

अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (ईरी) और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के संयुक्त प्रयास से विकसित इस प्रजाति का तीन वर्ष तक अखिल भारतीय स्तर पर परीक्षण किया गया। इसके बाद आईसीएआर की बैठक में इसे स्वीकृति मिल गई। बीएचयू के प्रो. श्रवण कुमार सिंह के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की टीम डॉ. जयसुधा एस, डॉ. धीरेंद्र कुमार सिंह, डॉ. आकांक्षा सिंह तथा अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (ईरी) फिलिपींस के वैज्ञानिक डॉ. अरविंद कुमार तथा डॉ विकास कुमार सिंह ने 15 साल की मेहनत के बाद यह नई किस्म विकसित हुई है। किसानों को इसका बीज अगले वर्ष खरीफ 2024 में उपलब्ध होगा।

देवास में सरपंच ने इस्तीफा देकर चुना शिक्षक का पद

देवास। जागत गांव हमार

आमतौर पर शासकीय सेवक नौकरी छोड़कर चुनाव के मैदान में उतरते हैं। परन्तु देवास जिले के आदिवासी अंचल के युवा सरपंच बादल मुजाल्दे ने सरकारी शिक्षक के रूप में चयन होने पर सरपंची से त्यागपत्र दे डाला। आदिवासी युवक कुछ महीने पहले हुए पंचायत चुनाव में जीतकर गांव का सरपंच बना था। इसके पूर्व पिछले 8 वर्ष युवक की पत्नी ने गांव की सरपंची संभाली थी। पत्नी के ही कहने पर युवक ने सरकारी शिक्षक परीक्षा में चयन होने पर सरपंची से त्यागपत्र दे दिया।

सरपंच बादल मुजाल्दे ने दिया त्यागपत्र

युवक को फिलहाल बड़वानी जिले में पदस्थापना मिली है। मामला देवास जिला मुख्यालय से करीब 100 किमी से भी ज्यादा दूर जिले की आखिरी पंचायत कनाड़ का है। इस पंचायत में कनाड़ के अलावा तिवड़िया और सेमलीखेड़ा गांव भी है। इसी पंचायत के तिवड़िया निवासी 31 वर्षीय आदिवासी सरपंच बादल मुजाल्दे ने पिछले महीने त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र देने के पीछे बड़ी रोचक वजह सामने आई है। दरअसल, मुजाल्दे का चयन सरकारी प्राथमिक शिक्षक के रूप में हो गया। चयन होने के बाद उन्होंने सरपंची से ज्यादा शिक्षक बनने को तरजीह दी और तुरंत त्यागपत्र देकर शिक्षा विभाग में जाइन कर लिया। कुछ ही दिन सरपंच रहने के बाद बागरसिंह शिक्षक बन चुके हैं।

रीवा जिले में बने 119 उपार्जन केन्द्र

रीवा। रीवा जिले के उपार्जन केन्द्रों में रबी सीजन के फसलों की खरीदी जारी है। किसानों से गेहूं खरीदी के लिए जिलेभर में 119 केन्द्र बनाए गए हैं। जिसमे पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर गेंहू की बारी-बारी से खरीदी की जा रही है। 8 मई तक 9551 किसानों से 478477 क्विंटल गेहूं उपार्जन केन्द्र आ चुका है। किसानों द्वारा विक्रय किए गए गेहूं के लिए 9432.75 लाख रुपए की राशि मंजूर की गयी है। जो किसानों के खाते में सीधे भेजी जा रही है। 119 केन्द्रों में खरीदे गए गेहूं में 409861 क्विंटल का परिवहन कर भंडारण कराया जा चुका है। बेमौसम बारिश को लेकर खरीदी केन्द्र के प्रभारियों को अलर्ट किया गया है। हालांकि जिले के कई खरीदी केन्द्र बेयर हाउस में बने है। वहीं ओपन जगहों पर हो रही खरीदारी को लेकर तिरपाल आदि की पहले से व्यवस्था बनाने के निर्देश है। जिला आपूर्ति नियंत्रक ओपी पांडेय ने बताया कि अब तक 16343 किसानों ने गेंहू उपार्जन के लिए स्लॉट बुक किए हैं। खरीदी केन्द्रों में गेंहू उपार्जन के लिए वारदाने, तौल कांटे और अन्य प्रकार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। किसान अपनी सुविधा के अनुसार खरीदी केन्द्र तथा खरीदी का स्लॉट बुक कर सकते हैं।

-बिजली की जहां पहुंच हो मुश्किल वहां लगाएं सोलर

बिजली का सस्ता-बेहतर विकल्प 'सोलर पावर ट्री'

डॉ.शशिकांत सिंह, समस्तीपुर। जागत गांव हमार

डॉ. राजेंद्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ. रमेश चंद्र श्रीवास्तव ने विश्वविद्यालय में योगदान देने के साथ ही सोलर ट्री के स्थापना पर विशेष बल दिया। विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध सरस्वती गार्डन में स्ट्रीट लैंप एवं फव्वारों को सोलर ट्री के माध्यम से संचालित करने के साथ साथ ढाब क्षेत्र में जहां बिजली पहुंचना बहुत मुश्किल है वहां पर रात्रि में प्रकाश के साथ साथ 3 हॉर्स पावर के समर्सेबल पंप के माध्यम से सिंचाई सोलर ट्री के माध्यम से किया जा है। सोलर ट्री को किसानों के मध्य लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से इसे विवि द्वारा संचालित विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों पर प्रकाश और 3 हॉर्स पावर के समर्सेबल पंप के माध्यम से सिंचाई करने के उद्देश्य से लगाया गया है। इसे लगाने में प्रारंभिक लागत कुछ ज्यादा है, लेकिन इसे लगा कर बिजली बिल में 15 से 20 प्रतिशत तक कमी लाई जा सकती है। सोलर ट्री के माध्यम से विवि की विभिन्न इकाइंयों में सफलतापूर्वक सौर ऊर्जा उत्पादित किया जा रहा है।

कम जगह में और कहीं भी लगाएं

इसे और किसानों के मध्य प्रचारित करने की आवश्यकता है। देश में ऊर्जा संकट की समस्या को हल करने के लिए सीएसआईआर-सीएमईआरआई वैज्ञानिक ने ऐसा सोलर पावर ट्री बनाया है। जो सौर ऊर्जा से बिजली की आपूर्ति करता है। इस सोलर ट्री की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसको बहुत ही कम जगह में और कहीं भी लगाया जा सकता है। पूर्व के अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है। सौर ऊर्जा के लिए जो सबसे बड़ी समस्या थी वह जमीन थी। सोलर पावर ट्री इस समस्या का बेहतर समाधान है।

सोलर पावर ट्री के फायदे

- बहुत कम जगह में ज्यादा से ज्यादा बिजली का उत्पादन किया जा सकता है।
- बिजली के बिल जमा करने की झंझट से मुक्ति
- सोलर ट्री का प्रयोग 30-35 साल तक आसानी से किया जा सकता है।
- तेज हवा या तूफान आने पर भी इसके गिरने का कोई डर नहीं है।
- दुर्गम स्थानों पर जहां बिजली पहुंचाना मुश्किल है यथा नदी के किनारे के ढाब क्षेत्र में, सड़कों के किनारे, ऊंची नीची जमीन पर सोलर ट्री आसानी से लगाए जा सकते हैं।
- सोलर पैनलों से अधिकतम लाभ के लिए आवश्यक है की पैनल हमेशा साफ सुथरे रहे, सोलर पैनल के ऊपरी हिस्से तक को साफ करने के लिए इसमें फव्वारा लगा होता है।
- सोलर पैनल सोलर ट्री की विभिन्न शाखाओं पर अधिक ऊंचाई पर लगे होते है इसलिए जमीन पर लगे पैनल की तुलना में उन्हें अधिक धूप मिलती है। इससे ज्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है।

सीएसआईआर-सीएमईआरआई के वैज्ञानिकों के अनुसार पूर्व में पांच किलोवाट सोलर पावर का उत्पादन करने के लिए 500 वर्ग फुट जमीन की आवशकता होती थी। लेकिन पांच किलोवाट का सोलर पावर ट्री लगाने के लिए मात्र चार वर्ग फुट की जरुरत होगी। सोलर पावर ट्री दूर से देखने पर एक पेड़ जैसा दिखाई देता है। जिसकी कई शाखाएं होती है। इसकी हर शाखा पर लगभग 30 सोलर पैनल लगे होते है। सोलर ट्री का विकास केन्द्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है।

प्रो. एसके सिंह सह निदेशक, अनुसंधान

सौर ऊर्जा बनाने के लिए देश मे किसी भी राज्य को हरित ऊर्जा पर बने रहने के लिए हजारों एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी, लेकिन सोलर ट्री लगाने के लिए बहुत कम जमीन पर लगा कर हजारों मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। सोलर ट्री को वर्ष 2008 में ही तैयार कर लिया गया था। लेकिन सरकार का ध्यान 2016 में गया जब केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने अपने आवास पर सोलर ट्री लगवा कर इसका उद्घाटन किया।

डॉ. राजेंद्र प्रसाद, केन्द्रीय कृषि विवि,पूसा,समस्तीपुर

बिजली के संकट को दूर करने में सोलर प्लांट की बड़ी भूमिका है। इसलिए देश के हर नागरिक को इसके बारे में विशेष तौर पर सोचना होगा। सरकार भी इस दिशा में प्रयास कर रही है। सबसे पहले 3 किलोवाट, 5 किलोवाट उसके बाद 7.5 किलोवाट तक के सोलर ट्री संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए है। 9 किलोवाट तक के सोलर ट्री तैयार करने के प्रयास चल रहे है। पांच किलोवाट तक के सोलर ट्री लगाने की लागत लगभग पांच लाख के आस पास आती है। लागत के संबंध में संस्थान के वैज्ञानिकों से या ऑनलाइन इंडिया मार्ट से संपर्क किया जा सकता है।

डॉ. हर्षवर्धन, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री

जमुई के 50 गांव होंगे बाल विवाह बाल श्रम-मानव व्यापार से आजाद

जमुई। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन फाउंडेशन (यूएस) दिल्ली एवं ग्राम नेहरू युवा ट्रस्ट जिला प्रशासन के सहयोग से जमुई जिले के 50 गांव को बाल विवाह मुक्त करने का निर्णय लिया है। संस्था मानव तस्करी, बाल श्रम, बच्चों की सुरक्षा विषयों पर भी जिला प्रशासन के सहयोग से जिले में कार्य करेगी। ग्राम नेहरू युवा ट्रस्ट के सचिव सुनील कुमार मिश्रा ने बताया कि नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने पूरे देश में बाल विवाह, मानव तस्करी को समाप्त करने और बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक अभियान शुरू किया है। उसी के तहत जमुई जिला में भी ग्राम नेहरू युवा ट्रस्ट को जिम्मेदारी दी गई है। सुनील कुमार मिश्रा ने बताया कि गत दिवस दिल्ली में एक समझौता पत्र पर संयुक्त हस्ताक्षर हुआ है। जिसमें जिला प्रशासन के साथ मिलकर रणनीति बनाकर जिला के 50 गांव को बाल विवाह मुक्त गांव बनाने का निर्णय लिया गया है। इसमें लगभग एक लाख से अधिक लोगों से बाल विवाह के खिलाफ शपथ पत्र भी भरवाने की योजना है। जिस विषय पर आज जमुई जिला के समाजसेवी साथी के साथ रुरल एम ग्राम के कार्यालय टाऊन हाल रोड कल्याणपुर में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता सुनिल कुमार मिश्रा ने किया। समाजिक कार्यकर्ता नंदलाल सिंह धनंजय कुमार गीता भारती सनेहलता दुर्गा कुमारी पुजा सिंह अनिमेंश कुमार आदि लोग मौजूद थे।

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

- जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।
- समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।
- ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, स्थानीय संपादक- **अरविंद मिश्र, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)